उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 19 | 1-15 अक्टूबर 2021 | ₹ 20/-

विजयादशमी के अवसर पर संघ प्रमुख का उद्‌बोधन

- मौलाना कलीम सिद्दीकी के मकान पर छापे
- मस्जिद में हुए धमाके में 100 से ज्यादा अफगान मरे
- यहूदियों को मस्जिद अल-अक्सा में प्रार्थना की अनुमति
- मुसलमानों में तलाक की बढ़ती घटनाओं पर चिंता

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

विजयादशमी के अवसर पर संघ प्रमुख का उद्‌बोधन 04
पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद की ज्वाला भड़काने का प्रयास 08
फैसल रहमानी बने इमारत-ए-शरिया के आठवें अमीर 11
गत सात वर्षों में कांग्रेस के 400 नेताओं ने पार्टी छोड़ी 13
दिल्ली में मौलाना कलीम सिद्दीकी के मकान पर छापे 14

विश्व

अफगानिस्तान की मस्जिद में हुए धमाके में 100 से ज्यादा नमाजी मरे 16
तालिबान और अमेरिका के बीच वार्ता 18
यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी 19
81 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों को एक टापू पर भेजने का फैसला 20
बलूचिस्तान में भीषण भूकंप 21
पाकिस्तान गुप्तचर एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त 22

पश्चिम एशिया

यहूदियों को मस्जिद अल-अक्सा में प्रार्थना की अनुमति 23
ईरान और तुर्की के साथ संबंध सुधारने हेतु यू.ए.ई. प्रयत्नशील 24
बहरीन में इजरायली दूतावास का उद्‌घाटन 25
ईरान द्वारा रूस के साथ संबंध सुधारने का प्रयास 26
ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री 28
सऊदी अरब में 16000 घुसपैठिए गिरफ्तार 29

अन्य

मुसलमानों में तलाक की बढ़ती घटनाओं पर चिंता 30
चारमीनार निर्माण के 430 वर्ष 30
अशरफ गनी पर 16 करोड़ डॉलर चोरी का आरोप 31
कुरान की अनमोल पांडुलिपि प्रदर्शनी में पेश 31
सऊदी अरब में 200 महिलाएं मस्जिदों की देखभाल के लिए नियुक्त 32
अमेरिका में मुसलमानों के कब्रिस्तान को आग लगाने का प्रयास 32

सारांश

हाल ही में उर्दू समाचारपत्रों की नीति में हुई तब्दीली के बारे में यह संकेत मिलता है कि अब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के भाषणों को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें प्रमुखता से प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। डॉ. भागवत ने विजयादशमी के अवसर पर जो उद्‌बोधन दिया उसे अधिकांश उर्दू समाचारपत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हालांकि उन्होंने अपने संपादकीयों में संघ को निशाना बनाने की अपनी पुरानी नीति को जारी रखा या उसकी उपेक्षा की। मोहन भागवत ने विजयादशमी उद्‌बोधन में अनेक महत्त्वपूण मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या में धार्मिक आधार पर असंतुलन को उन्हांने देश की एकता और अखंडता के लिए भारी खतरा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने घुसपैठ और धर्मांतरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने की वकालत की है। उन्होंने धारा 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर घाटी में हाल ही में आए आतंकवाद की लहर पर चिंता प्रकट करते हुए आशा व्यक्त की है कि मोदी सरकार इस पर काबू पा लेगी।

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत के प्रति पाकिस्तान का रूख आक्रामक होता जा रहा है। कश्मीर घाटी में गैरमुसलमानों की हत्याओं का सिलसिला पुनः शुरू हो गया है। हाल ही में एक स्कूल पर आतंकियों ने हमला करके अध्यापकों के पहचानपत्रों को जांच करने के बाद सिर्फ उन्हीं अध्यापकों को अपना निशाना बनाया जो मुसलमान नहीं थे। हाल ही में सीमा पार से पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। इस घुसपैठ को रोकने का प्रयास करते हुए हमारे सात से अधिक जवान शहीद हो चुके हैं। मोदी सरकार कश्मीर घाटी की स्थिति पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक पाकिस्तानी गुप्तचर को गिरफ्तार किया है जो गत 13 वर्षों से देश के विभिन्न भागों में रहकर जासूसी कर रहा था और उसने राजधानी में अनेक स्थानों पर विस्फोट करने की भी योजना बना रखी थी। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई द्वारा पोषित एक दर्जन से अधिक आतंकवादी पकड़े गए हैं। उनसे काफी गोला बारूद भी बरामद हुआ है।

बिहार इमारत-ए-शरिया के नेतृत्व के लिए विभिन्न गुटों में जो विवाद काफी देर से चल रहा था उसने एक नया मोड़ लिया है। इमारत-ए-शरिया के सातवें अमीर स्वर्गीय वली रहमानी के पुत्र ने निर्धारित कार्यक्रम से पूर्व ही चुनाव करवाकर आठवें अमीर का पद संभाल लिया है। उनके विरोधियों का आरोप है कि इस चुनाव में जबर्दस्त धांधलियां हुई हैं और अधिकांश मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने से वंचित रखा गया है। इससे इमारत-ए-शरिया में विभाजन का खतरा पैदा हो गया है। खास बात यह है कि इमारत-ए-शरिया के जो आठवें अमीर फैसल रहमानी चुने गए हैं उन्होंने किसी भी मदरसे से इस्लामिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है और न ही उनका देश की मुस्लिम राजनीति स ही कोई संबंध रहा है। उनकी शिक्षा-दीक्षा अमेरिका में हुई थी और अभी हाल तक वे अमेरिका मं नौकरी कर रहे थे।

अफगानिस्तान में दिन-प्रतिदिन स्थिति बिगड़ रही है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट चुन-चुनकर शियाओं को अपना निशाना बना रहा है। हाल ही में एक मस्जिद में जुमा की नमाज में हुए आत्मघाती हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। तालिबान और अमेरिका के बीच जो वार्ता शुरू हुई थी अभी तक उसका ठोस परिणाम निकलता नजर नहीं आ रहा है।

राष्ट्रीय

विजयादशमी के अवसर पर संघ प्रमुख का उद्‌बोधन

हाल ही में उर्दू समाचारपत्रों की नीति में एक परिवर्तन आया है और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के भाषणों को नजरअंदाज करने की बजाय महत्व देना शुरू किया है। इसका संकेत सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के विजयादशमी के उद्‌बोधन के कवरेज से मिलता है। उदाहरण के रूप में हैदराबाद के प्रमुख अखबार **सियासत** (16 अक्टूबर) ने इसे प्रमुख समाचार के रूप में प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'धर्मांतरण और घुसपैठ रोकने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जरूरी : मोहन भागवत।' दूसरा उपशीर्षक है, 'हसन मेवाती, खुदाबख्श, हकीम खान सूरी और अशफाक उल्लाह खान जैसे मुसलमानों पर हिंदुस्तान को गर्व है।'

समाचार के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने देश की जनसंख्या वृद्धि दर में धार्मिक असंतुलन पर चिंता प्रकट करते हुए उसे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया है और कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर धर्मांतरण और घुसपैठ रोकने के लिए जरूरी है। विजयादशमी के अवसर पर संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉ. भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है और इसके लिए जनसंख्या नीति बनानी चाहिए जो कि सभी पर समान रूप से लागू हो। उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या और विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या की दर में असंतुलन और विभिन्न सम्प्रदायों की जनसंख्या में वृद्धि की दर में भारी अंतर के कारण विदेशियों की घुसपैठ और धर्मांतरण का गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। डॉ. भागवत ने कहा कि 1951 और 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की दर में धार्मिक दृष्टि से काफी अंतर है। जबकि भारत के अन्य संप्रदायों के अनुयायियों की जनसंख्या की वृद्धि दर कम है। मगर मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बढ़ गया है।

उन्होंने कहा कि बाहर से आए सभी संप्रदायों के अनुयायियों सहित हर एक को यह समझना होगा कि हमारी आध्यात्मिक आस्थाओं और उपासना के तरीकों में मतभेद के बावजूद हमारे पूर्वज एक हैं जो एक सनातन परंपरा में पले बढ़े हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति में किसी को अजनबी नहीं माना जाता। भारतीयता में इसमें संतुलन है। उन्होंने कहा कि भारतीय होने पर आस्था रखने वाले विभिन्न धर्मों के लोग हमारे पूर्वजों की विचारधारा को समझते हैं। इसलिए किसी को किसी भाषा और उपासना पद्धति को त्यागने की जरूरत नहीं। मगर कट्टरवाद को छोड़ना जरूरी है। किसी के मुसलमान होने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं मगर राष्ट्रवादी विचारधारा जरूरी है। हिंदू समाज हर एक को अपना लेता है। बहुत से मुसलमान हमारे लिए अनुकरणीय हैं। यही कारण है कि इस देश ने हसन खान मेवाती, हकीम खान सूरी, खुदाबख्श, गौस खान और अशफाक उल्लाह खान देखे हैं। वे सब के लिए उदाहरण और अनुकरणीय हैं। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि आज भी देश को खंडित करने के प्रयास जारी हैं और ऐसे लोगों में एकता भी पैदा हुई है।

बेंगलरु से प्रकाशित **सालार** (16 अक्टूबर) ने भी मोहन भागवत के उदबोधन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मगर उसने इसके साथ ही मोहन भागवत को अपना निशाना भी बनाया है। समाचारपत्र ने कहा है कि मोहन भागवत ने अपने शरारतपूर्ण और अलोकतांत्रिक बयान में यह दावा किया है कि देश में अराजकता का वातावरण बनाया जा रहा है। कुछ कट्टरवादी देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हिंदुओं को ताकतवर और एकजुट होने की जरूरत है। इसी से देश की सभी समस्याआं का समाधान भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर में असंतुलन एक जटिल समस्या बन गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ के कारण आबादी बढ रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाम लिए बिना ड्रग्स ओर ओटीटी पलेटफॉर्म पर भी सरकार को नसीहत दे डाली। नागपुर में हुए इस कार्यक्रम में इजरायली राजनयिक कोब्बी शोशानी भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मोहन भागवत ने कहा कि शत्रुता और पृथकतावाद जो इस देश के विभाजन का कारण बना था उसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। विशेष रूप से नई पीढ़ी को यह मालूम होना चाहिए कि हमें छोटी-छोटी पहचान को भूलना चाहिए और आस्था, फिरकापरस्ती, जात-पात, भाषा और प्रांतों के आधार पर विघटनकारी प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। यह वर्ष हमारी आजादी का 75वां वर्ष है। यह आजादी हमें रातों-रात नहीं मिली। देश के सभी हिस्सों और विभिन्न संप्रदायों से आने वाले लोगों ने तपस्या और बलिदान के हिमालय को बुलंद किया है। आजादी की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। दुनिया में ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनके लिए भारत का विकास और उसके गौरवशाली स्थान तक पहुंचना पसंद नहीं है। यही कारण है कि दुनिया और हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने का प्रयास जारी है। हिंदुस्तान के लोगों को इतिहास और संस्कृति को लेकर गुमराह किया जा रहा है। इसलिए देश की

जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए और उसे समान रूप से सभी पर लागू किया जाना चाहिए।

संघ प्रमुख ने देश में नशे की बढती हुई प्रवृत्ति को रोकने का आग्रह किया और कहा कि मादक पदार्थों से होने वाली आय कहां जा रही है इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने बिटकॉइन के बारे में भी प्रश्न उठाए और कहा कि इस पर किसका नियंत्रण है मैं नहीं जानता। मगर सरकार को इस पर काबू पाना होगा और वह भी ऐसा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमें अपने स्तर पर इससे लड़ने क लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति किसी को अजनबी नहीं समझती इसलिए भारतीय संस्कृति के उत्थान से ही पूरे देश में समता आएगी। अगर हिंदुत्व उठेगा तो फिर इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। देश में जो मतभेद उभर रहे हैं उनके उन्मूलन की बेहद जरूरत है।

हमारा समाज (16 अक्टूबर) के अनुसार धर्मांतरण और घुसपैठ को रोकने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को संघ प्रमुख ने जरूरी करार दिया है और उन्होंने देश में जनसंख्या वृद्धि की दर में असंतुलन पर चिंता प्रकट की है और उसे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया है। उन्होंने मुसलमानों के आबादी में बढ़ते अनुपात पर भी चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के निरस्त किए जाने के बाद लोगों में जो भय का वातावरण समाप्त हो गया था उसे बढ़ाने के लिए देशद्रोही तत्व वहां के लोगों का लक्षित करके हत्या कर रहे हैं।

इत्तेमाद (16 अक्टूबर) ने भी मोहन भागवत के भाषण को मुख्य पृष्ठ पर बड़ी प्रमुखता से चार कॉलम शीर्षक देकर प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन का उन्हें बहुत बड़ा दुख है इसलिए हमें एकता और अखंडता के आधार पर देश का विकास करना चाहिए। सभी त्योहारों को एक साथ मनाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि सभी बिरादरी के लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में फंड इकठ्ठा करने में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जब हिंदुत्व का विकास होगा तो देश के शत्रुओं और मतभेद फैलाने वालों की दुकान बंद हो जाएगी।

औरंगाबाद टाइम्स (16 अक्टूबर) ने भी मोहन भागवत के भाषण को वृहद रूप से मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है और कहा है कि जात-पात देश की एकता में सबसे बड़ी रूकावट रही है और इसलिए इसे खत्म करना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने सिखों के नौवे गुरु तेगबहादुर के बलिदान का विशेष रूप से उल्लेख किया।

इससे पूर्व **मुंबई उर्दू न्यूज** (12 अक्टूबर) के अनुसार संघ प्रमख मोहन भागवत ने देहरादुन में 'हिंदू जागे तो विश्व जागे' विषय पर आयोजित एक समारोह में भाषण देते हुए इस बात पर चिंता प्रकट की है कि लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्मांतरण कर रहे हैं। हिंदुओं को अपने बच्चों को अपने धर्म और उपासना पद्धति के प्रति सम्मान और जागरूकता पैदा करना चाहिए। आज छोटे-छोटे लाभ और विवाह के लिए लोग धर्मांतरण कर रहे हैं जो कि बेहद चिंताजनक है। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। क्योंकि अपने बच्चों का लालन-पालन हम ही करते हैं। मगर उन्हें हम अपने धर्म पर गर्व करना नहीं सिखाते। हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति की रक्षा करनी होगी। आज भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैल रही है।

इससे पूर्व **औरंगाबाद टाइम्स** (13 अक्टूबर) के अनुसार उदय माहुरकर द्वारा लिखित पुस्तक 'वीर सावरकर : द मैन हू कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टिशन' का दिल्ली में विमोचन करते हुए संघ प्रमुख ने कहा था कि अगर सावरकर की बात सुनी गई होती तो देश का विभाजन नहीं होता। उन्होंने कहा कि सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीयता की सबसे पहले घोषणा की। उनका राष्ट्रवाद पूरे विश्व की एकता और मानवता पर आधारित था। 1857 के प्रथम सवतंत्रता संग्राम के

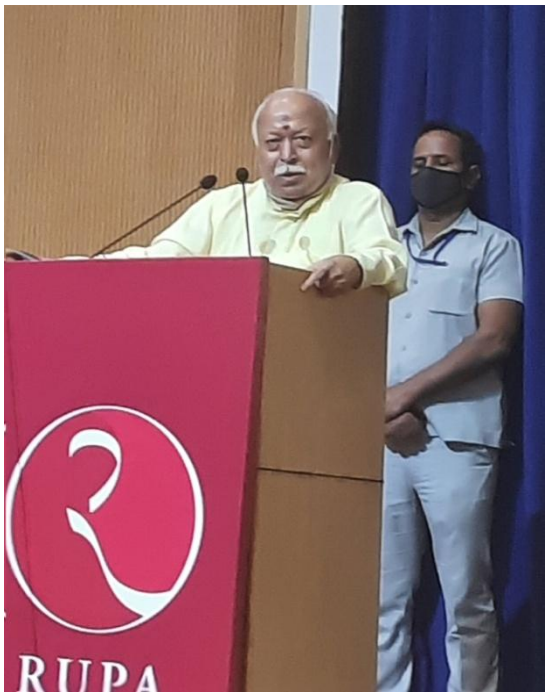

बारे में सावरकर ने लिखा था कि हिंदू राजाओं के भगवे झंडे और चांद तारे वाले हरे झंडे दोनों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। मगर बाद में खिलाफत आंदोलन के बाद वहाबी विचारधारा के कारण देश का वातावरण बिगड़ा और विभाजन हुआ। अगर हम सावरकर की नीतियों पर चलते हुए सबको समान अधिकार देते और किसी का शोषण नहीं करते तो देश का विभाजन नहीं होता। अगर हम एकता में अनेकता को स्वीकार कर लेते तो जिस तरह से दूसरे देशों में धर्म के आधार पर विभाजन हुआ वैसा यहां नहीं होता। उन्होंने कहा कि सावरकर ने मुसलमानों के समान अधिकार के साथ-साथ जिम्मेवारी में भी भागीदारी की बात कही।

कौमी तंजीम (14 अक्टूबर) के अनुसार मोहन भागवत ने कहा कि वीर सावरकर के हिंदुत्व सिद्धांत ने कभी भी लोगों के साथ उनकी संस्कृति और पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि सावरकर कहते थे कि हम एक ही मां के बेटे हैं। हम सभी भाई-भाई हैं। उपासना के भिन्न-भिन्न तरीके हमारी देश की परंपरा रही है और हम मिलकर देश के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर मुस्लिम विरोधी नहीं थे। उन्होंने उर्दू में कई गजलें भी लिखी हैं। कई लोगों ने भारतीय समाज में हिंदत्व और एकता के बारे में बातचीत की। मगर सावरकर ने इसके बारे में हमेशा भरपूर अंदाज में बात की। अब इतने वर्षों के बाद यह महसूस किया जा रहा है कि अगर हम सावरकर की विचारधारा का अनुकरण करते तो देश का विभाजन नहीं होता। देश के विभाजन के बाद भारत से जो लोग पलायन करके पाकिस्तान गए थे उनकी वहां कोई प्रतिष्ठा नहीं है। वहां पहले से बसे लोग उनसे भेदभाव करते हैं। आज भी भारत से पाकिस्तान गए लोगों को वहां हेय दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज एक हैं सिर्फ उपासना पद्धति में अंतर है। सनातन धर्म की उदार दृष्टि और संस्कृति पर हमें गर्व है और यह विरासत हमें विकास की ओर ले जाती है।

पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद की ज्वाला भड़काने का प्रयास

आश्चर्यजनक रूप से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर भड़काए जा रहे आतंकवाद की घटनाओं को आमतौर पर उर्दू के समाचारपत्रों ने नजरअंदाज किया है।

सियासत (27 सितंबर) के अनुसार भाजपा के एक नेता वसीम बारी, उनके भाई और पिता की पाकिस्तानी आतंकियों ने जिला बांदीपुर में हत्या कर दी थी। जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रमुख दिलबाग सिंह के अनुसार बाद में बांदीपुर में इस हत्या से जुड़े हुए आजाद शाह और आबिद हक्कानी नामक आतंकवादियों को मार गिराया गया। अजीब बात यह है कि जब वसीम बारी पर

हमला हुआ तो उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा तैनात दस के दस पुलिसकर्मी घटनास्थल से गायब थे। पुलिस के दावे के अनुसार इन सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

रोजनामा सहारा (11 अक्टूबर) के अनुसार पुलिस ने यह स्वीकार किया है कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर घाटी में सात निर्दोष लोगों की हत्या की है। इनमें से चार का संबंध श्रीनगर से बताया जाता है। बताया जाता है कि उनकी हत्या करने से पूर्व आतंकियों ने उनके पहचानपत्रों की जांच की और सिर्फ उन्हीं लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया जो गैर मुसलमान थे। इनमें एक स्थानीय स्कूल की सिख मुख्य अध्यापिका रूपिंदर कौर भी शामिल हैं। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर में जो चार अल्पसंख्यक मारे गए थे उनकी हत्या की जिम्मेवारी टीआरएफ नामक एक आतंकवादी संगठन ने स्वीकार की है। इस संगठन का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से बताया जाता है। श्रीनगर में जो लोग मारे गए उनमें एक महिला सहित दो अध्यापक, एक कश्मीरी दवा विक्रेता और गोलगप्पे बेचने वाला एक बिहारी व्यक्ति वीरेन्द्र पासवान शामिल है।

इससे पूर्व इस वर्ष के प्रारम्भ में भी आतंकियों ने एक दर्जन से अधिक गैर मुसलमानों को मार दिया था। इन घटनाओं के बाद जम्मू कश्मीर घाटी से हिंदुओं और सिखों का पलायन शुरू हो गया है। 1990 के बाद यह पहली बार है जब कश्मीर घाटी से गैर मुसलमानों को सामुहिक रूप से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। पलायन करने वाले परिवारों की संख्या के बारे में भिन्न-भिन्न दावे किए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार घाटी से पलायन करने वालों में 1400 परिवार शामिल हैं। जबकि अन्य स्रोतों ने इनकी संख्या 10000 के करीब बताई है।

इंकलाब (13 अक्टूबर) के अनुसार शोपियां में मुठभेड़ में पांच आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है। इनका संबंध आतंकवादी संगठन टीआरएफ से बताया जाता है। पहली मुठभेड़ में तोन लोग मारे गए। इनके कब्जे से अस्त्र-शस्त्र भी बरामद हुए हैं। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार के अनुसार जो लोग मारे गए हैं उनमें से एक की पहचान मुख्तार शाह के रूप में हुई है, जिसने कुछ दिनों पूर्व श्रीनगर में गोलगप्पे बेचने वाले एक बिहारी वीरेन्द्र पासवान को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उन्होंने यह भो कहा कि जो लोग मुठभेड में मारे गए हैं उनका हाथ पूंछ में मारे गए भारतीय सैनिकों पर हमले में भी बताया जाता है। श्रीनगर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय के अनुसार जब कुछ पाकिस्तानी सीमा पार से घुसपैठ कर रहे थे तो भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसमें छह सैनिक शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि हम सीमा पार से किसी भी विदेशी घुसपैठिए को हर कीमत पर घुसपैठ करने से रोकेंगे। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिंता प्रकट करते हुए यह आरोप लगाया है कि प्रशासन की लापरवाही इन घटनाओं के लिए जिम्मेवार है।

देश की राजधानी में पाकिस्तान के इशारे पर खून की होली खेलने की जो योजना बनाई गई थी उसे दिल्ली पुलिस के विशेष सेल ने विफल बना दिया है।

इंकलाब (13 अक्टूबर) के अनुसार स्पेशल सेल ने लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क से पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित मोहम्मद अशरफ उफ अली अहमद को गिरफ्तार किया है जो कि मूल रूप से पाकिस्तान के नगर नारोवाल का रहने वाला है। यह गत 15

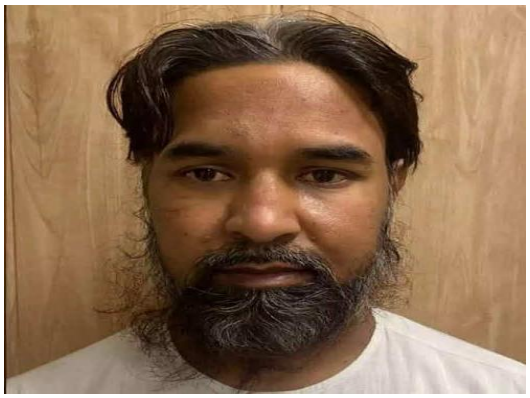

वर्षों से भारतीय नागरिक के रूप में रह रहा था। पुलिस की जानकारी के अनुसार यह बांगलादेश के रास्ते नेपाल में दाखिल हुआ था और वहां से बिहार होत हुए दिल्ली पहुंचा। बताया जाता है कि देवबंद में निवास के दौरान उसने फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बनवाए थे। उसने लोनी में रहने वाली एक महिला से निकाह भी किया था, जिसे छह महीने के बाद उसने छोड़ दिया। इसके बाद यह शास्त्री नगर में रहा और उसने वहां पर अली अहमद नूरी के नाम पर जाली पहचान पत्र भी बनवाए। वह मौलाना के रूप में विभिन्न मदरसों में काफी समय तक नमाज अदा करवाता रहा और पाकिस्तानी गुप्तचर विभाग को महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता रहा। अदालत में दिल्ली पुलिस ने उसका दो सप्ताह का रिमांड प्राप्त किया है और पूछताछ के दौरान उससे पुलिस को काफी जानकारी मिली है।

इंकलाब (14 अक्टूबर) के अनुसार यह पाकिस्तानी गुप्तचर 2010 से दिल्ली में गुप्तचर गतिविधियों में जुटा हुआ था। उसे पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी एक विदेशी एजेंसी द्वारा नियमित रूप से धनराशि भेजवातो थी। वह दिल्ली के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और बंगाल में भी कई स्थानों पर रहकर जासूसी करता रहा। इसके कब्जे से एके 47 और बम बनाने के काफी उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 सितंबर) के अनुसार मुंबई एटीएस द्वारा पाकिस्तान में प्रशिक्षित एक आतंकी जाकिर शेख को जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया गया है। उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। जाकिर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर छापे मारकर कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें प्रयागराज से उमेद उर रहमान और शाहरूख के साथ-साथ कई अन्य लोग भी शामिल हैं। गणेशोत्सव के दौरान महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर बम धमाके करने की साजिश करने वाले जान मोहम्मद को कोटा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। वह मूल रूप से मुंबई का रहने वाला है। प्रयागराज में पकड़ा गया उमेद उर रहमान लखनऊ में पकड़े गए आतंकवादी आमिर बेग का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी गिरोह के अनेक लोगों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक मुकुल गोयल के अनुसार अब तक इस संबंध में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें ताहिर, जमील, इम्तियाज, जीशान, आमिर और मूलचंद शामिल हैं। इनलोगों को लखनऊ, रायबरेली और प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है।

हमारा समाज (16 सितंबर) के अनुसार जिला बहराइच के अबु बकर नामक जिस आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसके परिवारजनों का कहना था कि अबु बकर दिल्ली में तब्लीगी सेंटर जा रहा था और उसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रहा है। जबकि पुलिस का दावा है कि अबु बकर हाल ही में पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटा था और उसके कब्जे से काफी विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। प्रयागराज में पकड़े गए जीशान कमर के बारे में कहा जाता है कि वह एक वर्ष पूर्व दुबई से भारत वापस आया था। उसकी निशानदेही पर उत्तर प्रदेश एटीएस ने नैनी क्षेत्र से बम बनाने का काफी सामान बरामद किया है।

फैसल रहमानी बने इमारत–ए–शरिया के आठवें अमीर

निर्धारित कार्यक्रम से पहले ही चुनाव करवाकर फैसल रहमानी इमारत-ए-शरिया के आठवें अमीर चुने गए हैं। वे सातवें अमीर मौलाना वली रहमानी के पुत्र हैं। उनका दावा है कि इमारत-ए-शरिया के 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी अमीर का चुनाव मतदान द्वारा हुआ है। हालांकि इससे पूर्व सभी अमीर सर्वसम्मति से ही निर्वाचित होते आ रहे थे। खास बात यह है कि इमारत-ए-शरिया के नए अमीर ने किसी मदरसे में इस्लामिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है बल्कि वे एक अमेरिकी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त हैं।

इंकलाब (10 अक्टूबर) के अनुसार इमारत-ए-शरिया के अमीर के पद पर फैसल रहमानी के चनाव से इमारत-ए-शरिया में चल रही गुटबाजी को नया बल मिला है और उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

दैनिक हिंदुस्तान (10 अक्टूबर) के अनुसार इमारत-ए-शरिया के सदस्यों की कुल संख्या 851 है, जिनमें से 558 ने ही मतदान किया। जबकि 293 अनुपस्थित रहे। इन सदस्यों को अरबाब-ए-हल्ल-ओ-अक्द कहा जाता है। फैसल रहमानी के विरोधी और पूर्व उपअमीर मौलाना अनीस उर रहमान कासमी को 196 मत प्राप्त हुए। जबकि फैसल रहमानी को 347 मत प्राप्त हुए।

इंकलाब (21 सितंबर) के अनुसार पूर्व नायब अमीर-ए-शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी ने यह घोषणा की थी कि नए अमीर का चुनाव 10 अक्टूबर को रांची में करवाया जाएगा। मगर

उनके विरोधी गुट ने 9 अक्टूबर को ही पटना में एक समानांतर अधिवेशन बुलाकर चुनाव की घोषणा कर दी थी। इस पर दोनों गुटों के बीच काफी मारपीट हुई थी। मौलाना फहद रहमानी ने पटना के एक होटल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रांची में 10 अक्टूबर को बुलाए गए अधिवेशन को असंवैधानिक घोषित किया था। इस विवाद को टालने के लिए नायब अमीर और उनके समर्थक शिबली कासमी ने इमारत-ए-शरिया कार्यसमिति का 30 अक्टूबर को एक अधिवेशन रांची में बुलाया। मगर इस अधिवेशन से पूर्व ही दूसरे गुट ने पटना में चुनाव करवाकर संगठन पर कब्जा कर लिया।

अभी हाल तक फैसल रहमानी अमेरिका में नौकरी करते थे। बैठक में तीन नाम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अनीस उर रहमान कासमी और सैयद अहमद वली फैसल रहमानी के नाम पेश किए गए थे। बाद में कुछ लोगों ने शमशाद रहमानी और मौलाना नजर तौहीद के नाम भी पेश किए। मगर हंगामे के दौरान इस बात को घोषणा की गई कि अमीर-ए-शरोयत के चुनाव में सिर्फ दो उम्मीदवार सैयद फैसल रहमानी और मौलाना अनीस उर रहमान कासमो ही मैदान में रह गए हैं। मतदान में भारी हंगामा हुआ। चुनाव करवाने के लिए तीन पयवेक्षक मौलाना युसूफ (अमीर-ए-शरोयत, असम), मौलाना सागीर (अमीर-ए-शरोयत, कर्नाटक) और मौलाना अतीकुर रहमान बस्तावी को नियुक्त किया गया था। मगर हंगामे के कारण उनकी नहीं सुनी गई। विरोधी गुट ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए उसका बहिष्कार किया। जबकि बैठक में उपस्थित अनेक लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया। मतदान का बहिष्कार करते हुए मौलाना अयूब निजामी ने कहा कि यह चुनाव संविधान के खिलाफ है इसलिए मैं इसका बहिष्कार करता हूं।

बताया जाता है कि इस मतदान में काफी हंगामा और मारपीट भी हुई। कहा जाता है कि इस चुनाव में फैसल रहमानी के भाई सैयद फहद रहमानी कुछ बाउंसरों को लेकर आए और उन्होंने हंगामा करवाया।

मौलाना फैसल रहमानी को उनके खिलाफ इमारत-ए-शरिया में उभर रहे विरोध का अहसास है। इसलिए उन्होंने इमारत-ए-शरिया के पदाधिकारियों को उनके हाथ पर शपथ लेने और यह घोषणा करने पर जोर दिया है कि व अमीर-ए-शरोयत के प्रत्येक आदेश को मानेंगे।

इंकलाब (12 अक्टूबर) के अनुसार इमारत-ए-शरिया के नवनिर्वाचित अमीर अपने सहयोगियों के साथ पटना की दरगाह मजीदिया में पहुंचे जहां दरगाह के सज्जादानशीन सैयद आयतुल्लाह कादरी ने उनके सिर पर रूमाल रखकर उन्हें इत्र पेश किया। बाद में नए अमीर ने दरगाह परिसर में स्थित अनेक कब्रों पर जाकर फातिहा भी पढ़ा।

गत सात वर्षों में कांग्रेस के 400 नेताओं ने पार्टी छोड़ी

इंकलाब (10 अक्टूबर) ने दावा किया है कि कांग्रेस का कैडर जिनमें प्रमुख नेता भी शामिल हैं हताश होकर कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। गत सात वर्षों में कांग्रेस के 399 प्रमुख नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ी है और अन्य पार्टियों का दामन थामा है। सबसे अधिक कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए हैं। दल बदलने की हमारी परंपरा हालांकि बहुत पुरानी है और इसको रोकने के लिए कई कानून भी बनाए जा चुके हैं। मगर हाल में दल बदलने की प्रवृत्ति में तेजी आई है। इसकी पुष्टि नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा जारी की गई रिपोर्टों से भी होती है। केंद्र में सत्ता से वंचित होने के बाद कांग्रेसी दूसरा ठिकाना तलाश कर रहे हैं। 2014 के बाद देश के बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य का सबसे जयादा प्रभाव कांग्रेस पर पड़ा है। जबकि भाजपा ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में कांग्रेस के 399 नेताओं ने अपनी पार्टी से नाता तोड़ा। इनमें 222 संसद और विधान सभा का चुनाव कांग्रेस क टिकट पर लड़ चुके थे जबकि 177 नेता ऐसे थे जो कि कांग्रेस के टिकट पर सांसद और विधायक रह चुके थे। हालांकि इस अवधि में अन्य पार्टियों से संबंधित 115 नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए। इस अवधि में दूसरी पार्टियों से छोड़कर भाजपा में जाने वालों का तांता लगा रहा। भाजपा में 173 सांसदों और विधायकों के साथ कुल 253 नेताओं ने भाजपा का दामन था। जबकि इस अवधि में 33 सांसदों और विधायकों सहित 111 नेताओं ने भाजपा का दामन छोड़कर अन्य पार्टियों का दामन थामा। इनमें मुकुल रांय और बाबुल सुप्रियो जैसे बड़ नेता भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भाजपा को छोड़कर कैडर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहा है। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा क्षति मायावती की बहुजन समाज पार्टी को उठानी पड़ी है। 2014 के बाद बसपा के सांसद और विधान सभाओं के 153 उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़ी और 20 विधायकों ने बसपा छोड़कर अन्य पार्टियों का दामन थामा। जबकि इस अवधि में 65 नेता बसपा में शामिल हुए। देश के विभिन्न राजनीतिक दलों में तृणमूल कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी है जिसमें जो लोग पार्टी

छोड़कर गए थे उनमें से अधिकांश वापस लौट आए हैं। गत सात वर्षों में इसके 26 सांसदों और विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी। जबकि 54 नेता वापस आ गए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय राजनीति की यह परंपरा बन गई है कि केवल सत्ता के साथ रहते हुए ही समाज सेवा की जा सकती है। इसलिए सत्ता से वंचित पार्टियों के नेता सत्तारूढ़ पार्टी में जाते हुए प्राय: यह तर्क देते हैं कि क्योंकि पुरानी पार्टी में रहकर मैं जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूं इसलिए इस पार्टी को छोड़ रहा हूं। जबकि कुछ लोग यह तर्क भी देते हैं कि मतदाताओं के दबाव के कारण उन्हें दल बदल करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस तरह का तर्क देने वालों में कई पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री तक शामिल हैं। यह तर्क एस.एम. कृष्णा ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होत हुए दिया था। मजेदार बात यह है कि मोदी मंत्रिमंडल में सत्ता की मलाई चाटने वाले भाजपा के सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी यही तर्क तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते समय दिया। मुकुल रांय की राय भी कुछ ऐसी ही थी।

कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे नेताओं में से अधिकांश सत्ता के बिना नहीं रह सकते। अब उनके लिए विचारधारा और नैतिकता का कोई महत्व ही नहीं रहा है। वे उसी झंडे को थामते हैं जो सत्तारूढ़ दल का हो और वही नारा लगाते हैं जिसका उन्हें फायदा मिले। यही कारण है कि हमने शंकर सिंह वाघेला जैसे संघ के कट्टर नेता और शिवसेना के नारायण राणे को सेक्युलरिज्म का पाठ जपते हुए देखा है और कल्याण सिंह और साक्षी महाराज जैसे लोग मुलायम सिंह के दरबार में हाजिरी देने पर मजबूर हुए हैं।

समाचारपत्र के अनुसार जिन कुछ बड़े कांग्रेसी नेताआं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, उनमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और 2012 से 2014 तक उत्तराखंड के कांग्रेसी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उनकी बहन तथा उत्तर पदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी भी शामिल हैं। ये दोनों इस समय भाजपा में हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एस.एम. कृष्णा ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा। इसके अतिरिक्त कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वालों में ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद और राधाकृष्ण विखे पाटिल शामिल हैं।

दिल्ली में मौलाना कलीम सिद्दीकी के मकान पर छापे

इंकलाब (6 अक्टूबर) के अनुसार धर्मांतरण करवाने के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी के दिल्ली सहित चार आवासों और कार्यालयों पर उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम ने दिल्ली पुलिस क सहयाग से छापा मारा और वहां से कई इलेक्टॉनिक उपकरण और महत्त्वपूर्ण दस्तावेज

बरामद करने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि इन छापों के दौरान जो दस्तावेज और उपकरण जब्त किए गए हैं उनकी जांच की जा रही है। ये छापे अदालत के निर्देश पर ओखला में उनके आवास जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट के दफ्तर ग्लोबल पीस सेंटर और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तरों पर मारे गए थे। यह छापामारी चार कमांडो दस्तों के साथ की गई। हाल ही में महाराष्ट्र से धीरज देशमुख को भी इस गिरोह से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। धीरज देशमुख ने हाल ही में मौलाना कलीम के दबाव पर इस्लाम कबूल किया था और वह वाट्सऐप द्वारा कई ग्रुपों को इस्लाम स्वीकार करने का आमंत्रण देता था।

एटीएस के पुलिस महानिदेशक जी.के. गोस्वामी के अनुसार धीरज से पूछताछ करने के लिए पुलिस ने सात दिन का रिमांड मांगा है। इसके अतिरिक्त मौलाना कलीम के एक अन्य नजदीकी सहयोगी हाफिज इदरिस कुरैशी को भी एक सप्ताह के रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने अदालत मं पेश किया था और उसके रिमांड की अवधि में चार दिन का विस्तार करने का अनुराध किया था जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। गोस्वामी ने कहा कि इन दोनों से पूछताछ के दौरान कई महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है।

इंकलाब (8 अक्टूबर) के अनुसार मौलाना कलीम के सहयोगी सरफराज जाफरी को भी पुलिस ने जामिया नगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जाफरी मौलाना के ग्लोबल पीस सेंटर के प्रबंधक के रूप में कार्य करता था और वह धर्मांतरण करने वालों के लिए नौकरी, रोजगार एवं शादो आदि के लिए व्यवस्था करता था। पुलिस के दावे के अनुसार उसे बाटला हाउस से गिरफ्तार किया गया है और वह अमरोहा का रहने वाला है और 2016 से वह मौलाना कलीम के सेंटर का प्रबंधक है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि मौलाना ने 'ह्यूमिनिटी फॉर ऑल' नामक एक एनजोओ बना रखा है, जिसके द्वारा धर्मांतरण करवाया जाता है। जो लोग इस्लाम स्वीकार करते हैं उन्हें उमर गौतम के दफ्तर में भेजा जाता है जो कि उन्हें जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवाता है। जबकि सरफराज जाफरी धर्मांतरण करने वालों को नकद सहायता दिया करता था। इससे पूर्व भो सरफराज जाफरी को पुलिस ने हिरासत में लेकर चार दिन तक पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया था।

विश्व

अफगानिस्तान की मस्जिद में हुए धमाके में 100 से ज्यादा नमाजी मरे

इंकलाब (9 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान में कुंदुज की मस्जिद में बम धमाके में 100 से अधिक नमाजियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मरने वालों में अधिकांश शिया हैं। जबकि जख्मी होने वालों की संख्या 200 से भी अधिक बताई जाती है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह विस्फोट आत्मघातो दस्ते के फिदायीन ने किया है। इस धमाके के बाद तालिबान ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारो है। तालिबान के अनुसार अफगानिस्तान स अमेरिकी और नाटो के सैनिकों के निष्कासन के बाद यह सबसे बड़ा घातक हमला है। बताया जाता है कि नमाजियों में इस्लामिक स्टेट के कुछ आत्मघाती हमलावर शामिल हो गए थे और उन्होंने ही इस हमले को अंजाम दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संपूर्ण मस्जिद में चारों तरफ मृतकों क अंग और उनका खून फैला हुआ है। मृतकों की संख्या में और भी वृद्धि होने की संभावना है। क्योंकि अस्पताल में जिन घायलों को दाखिल किया गया है उनमें से अधिकांश की हालत बेहद गंभीर है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इससे पूर्व भी इस्लामिक स्टेट का खुरासान प्रांत अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तारूढ़ होने के बाद एक दर्जन से अधिक धमाके कर चुका है और उसने इस धमाके की जिम्मेवारी भी ली है। अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट गत कुछ महीनों से शियाओं को अपना निशाना बनाता आ रही है और वह सैकड़ों शियाओं की हत्या कर चुका है।

तालिबान ने नमाज के दौरान हुए धमाके की निंदा करते हुए कहा है कि धमाका करने वाले

इस्लाम के दुश्मन हैं। 3 अक्टूबर को राजधानी काबुल में भी एक मस्जिद में एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। यह धमाका काबुल की ईदगाह मस्जिद के समीप हुआ था। यहां तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद की मां के निधन के बाद नमाज-ए-जनाजा की जा रही थी। विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान के सामने इस समय सबसे बड़ा खतरा इस्लामिक स्टट है जो धीरे-धीरे अफगानिस्तान में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 अक्टूबर) के अनुसार जलालाबाद में कुछ अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें कम-से-कम चार लोग मारे गए, जिनमें एक पत्रकार भी शामिल है।

सियासत (1 अक्टूबर) के अनुसार तालिबान ने अपने स्पेशल फोर्सेस को यह निर्देश दिया है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का उन्मूलन करने के लिए देश भर में पूरी गति से अभियान चलाया जाए। जर्मन संवाद समिति 'बीपीए' के अनुसार बिलाल करीमी नामक तालिबान प्रवक्ता ने दावा किया है कि तालिबान ने देश भर में इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने वाले लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया है। देश भर में अनेक स्थानों पर तालिबान फोर्सेस और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों में मुठभेड़ हुई ह, जिनमें काफी लोग मारे गए हें और सैकड़ों गिरफ्तार किए गए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यह अभियान किन-किन क्षेत्रों में शुरू किया गया है। मगर बिलाल करीमी का कहना है कि हालांकि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टट का कोई गढ़ नजर नहीं आता मगर उसकी दिखाई न देने वाली मौजूदगी को भी नजरअंदाज करना अफगानिस्तान के हित में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें यह आशा थी कि अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन के बाद इस्लामिक स्टेट के हमले कम हो जाएंगे। मगर हमारी यह आशा पूरी नहीं हुई। बल्कि इन हमलों में और भी तेजी आई है।

हमारा समाज (12 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अभी हमारे लिए यह दावा करना कठिन है कि अफगानिस्तान की राजनीति किस मोड़ लेती है। अब अफगानिस्तान में अमेरिका मौजूद नहीं है। इसके कारण जो रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको कौन पूरा करेगा यह कहना कठिन है। उन्होंने पाकिस्तान टीवी पर एक इंटरव्यू में कहा कि इस्लामिक स्टेट से छुटकारा पाने के लिए तालिबान ही एक विकल्प है। पश्चिम एशिया के इस्लामिक देशों के लिए अफगानिस्तान ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा वह हिंद महासागर और पाकिस्तान से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर विश्व की शक्तियों ने अफगानिस्तान में तालिबान को अकेला छोड़ दिया और उन्हें मान्यता नहीं दो या उन पर प्रतिबंध लगा दिया तो उसके कारण दुनिया भर को गंभीर परिणामों से गुजरना पड़ेगा। यह एक नाजुक क्षण है। अफगानिस्तान की घटना से सबसे ज्यादा धक्का अमेरिका को लगा है। क्योंकि उसकी आशा के विपरीत तालिबान अचानक अफगानिस्तान में सत्ता में आ गए हैं। वे इस बात को हजम नहीं

कर पा रहे हैं इसलिए वे बेहद गुस्से, हैरानी और सदमे की हालत में हैं। उन्होंने कहा कि अभी मेरी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से कोई बात नहीं हुई। अमेरिका एक सुपर पावर है वह हमसे कब बातचीत करता है या नहीं करता है यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। अफगानिस्तान के हालात पर टिप्पणी करते हुए इमरान खान ने कहा कि यह हकीकत है कि गनी सरकार का नियंत्रण सिर्फ नगरों तक ही सीमित था जबकि पूरा ग्रामीण अंचल तालिबान के कब्जे में था। हैरानी की बात यह है कि अब जो लोग मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं और जा यह दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की भूमि को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वे अभी तक क्या कर रहे थे?

उन्होंने कहा कि यह मामला आज का नहीं बल्कि दो दशक पुराना है। दो अरब डॉलर खर्च करने और लाखों लोगों को मरवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर वहां पर अफरातफरी फैलती है तो इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठन छा जाएंगे। जो कि हम सब के लिए और खासकर के पाकिस्तान के लिए बेहद परेशानी वाली बात होगी। एक दृढ़ अफगान सरकार ही इस्लामिक सटेट से निपट सकती है और यह साफ है कि तालिबान ही इस्लामिक स्टेट से छुटकारा पाने के लिए बेहतरीन विकल्प है।

तालिबान और अमेरिका के बीच वार्ता

इंकलाब (13 अक्टूबर) के अनुसार तालिबान और अमेरिका के बीच हुई वार्ता के पहले चरण में विशेष प्रगति नहीं हुई है।

सहाफत (12 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका ने यह साफ किया है कि तालिबान से वार्ता का मतलब उनकी सरकार को मान्यता देना नहीं है। दूसरी ओर तालिबान ने दावा किया है कि अमेरिका ने तालिबान को मानवीय आधार पर सहायता देना स्वीकार कर लिया है। अगस्त में अमेरिकी सेना के निष्कासन के बाद उसकी तालिबान के साथ दोहा में जो बातचीत हुई थी उसका पहला चरण पूरा हो चुका है। कतर में होने वाली इस वार्ता में अफगानिस्तान को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न करने और अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकालने और अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर सहायता उपलब्ध करवाने के बारे में वार्ता हुई है। तालिबान का दावा है कि अमेरिका ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि वह अफगानिस्तान के नागरिकों को सरकारी सहायता के साथ-साथ अन्य संगठनों द्वारा भी सहायता उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। किंतु अमेरिका की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि मानवीय आधारों पर अफगानिस्तान के नागरिकों को हम सहायता उपलब्ध कराने के बारे में वार्ता कर रहे हैं। अफगानिस्तान के नए विदश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि दोनों पक्षों ने 2020 में हुए दोहा सम्मेलन का पालन करने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते में तालिबान को इस बात के लिए पाबंद कराया गया था कि वह भविष्य में अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे आतंकवादी गिरोहों पर लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। ताकि वे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा न बन सकें।

सियासत (11 अक्टूबर) के अनुसार दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच शुरू हुई वार्ता में तालिबान ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका ने अपने देश में अफगान पूंजी को निकालने पर जो पाबंदियां लगा रखी हैं उनको हटाया जाए ताकि इस फंड का इस्तेमाल अफगानी जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जा सके।

इत्तेमाद (11 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने अमेरिका को इस बात की चेतावनी दी है कि वह अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश न करे अगर उसने ऐसा किया तो यह किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तालिबान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है कि वह इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को लगाम लगाने के लिए अफगानिस्तान को सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है और हम विदेशियों से सहायता लेकर इसे और नहीं उलझा सकते। तालिबान के प्रतिनिधियों ने अमेरिका से कहा है कि अमेरिका ने अफगान बैंक के फंड्स को निकालने पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं, उन्हें फोरन हटाया जाए। क्योंकि उन्हें हटाना अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि हमने तालिबान से अनुरोध किया है कि वह अफगानिस्तान में फंसे हुए अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकालन के लिए अमेरिका को सहयोग प्रदान करे।

इंकलाब (13 अक्टूबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने संयुक्त राष्ट्र संघ से जो वायदे किए थे उसे पूरा नहीं किया है। अफगान महिलाओं और लड़कियों को वह सुविधाएं देने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण 30 लाख अफगान लड़कियों की शिक्षा खटाई में पड़ गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद हालांकि तीन बार मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा चुका है मगर न तो किसी महिला को ही शामिल किया गया है और न ही उसमें किसी अल्पसंख्यक को ही भागीदार बनाया गया है।

यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी

इंकलाब (9 अक्टूबर) के अनुसार फ्रांस में निमाणाधीन यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद के प्रबंधकों को एक पत्र मिला है, जिसमें यह धमकी दी गइ है कि इस निर्माणाधीन मस्जिद का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। यह मस्जिद फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में तुर्की की सहायता से निर्माण की जा रही है और इसे आईयूप सुल्तान मस्जिद का नाम दिया गया है। इस पत्र में कहा

गया है कि इस मस्जिद का निर्माण कराने वाले सभी लोगों को मार दिया जाएगा और निर्माणाधीन भवन को बमों से उड़ा दिया जाएगा। हम मस्जिदों के खिलाफ हैं और हम यूरोप में इस्लाम को आतंकवाद फैलाने की कभी अनुमति नहीं देंगे। फ्रांस में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। फ्रांस में रहने वाले 40 लाख मुसलमानों को या तो फ्रांस से निकलना होगा या उन्हें इस्लाम धर्म छोड़ना होगा। हम जानते हैं कि आप इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपकों फ्रांस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह मस्जिद इस वर्ष के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी और उसका 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस मस्जिद में 5 हजार लोग नमाज अदा कर सकेंग और इसमें एक संग्रहालय, पुस्तकालय और रेस्टोरेंट भी होगा।

81 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों को एक टापू पर भेजने का फैसला

इंकलाब (10 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लदेश और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच हुए समझौत के बाद 81 हजार से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी के एक द्वीप में भेजने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। फ्रांसीसी संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार पुनर्वास के कार्यक्रम से संबंधित संगठनों की चिंता के बावजूद म्यांमार से आए 19 हजार मुस्लिम शरणार्थी पहले ही शरणार्थी कैंपों से समुंद्र के चार द्वीपों में भेजे जा चुके हैं। बांग्लदेश के शरणार्थी आयुक्त शाह रिजवान हयात के अनुसार अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों के समाप्त होने के बाद हम एक लाख शरणाथियों को फरवरी के आखिर तक इन चार टापुओं मं भेज देंगे। ये टापू 53 वर्ग कि. मी. तक फैले हुए हैं और ये दो दशक पूर्व समुद्र से निकले थे। ये टापू बांग्लादेश की मुख्य भूमि से 60 किमी दूर हैं और उन्हें पुनर्वास के योग्य बनाने पर अब तक 35 करोड़ डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों का आरोप है कि बांग्लादेश सरकार उन्हें जबरन इन गैर आबाद टापुओं में भेज रही है। इस समय साढ़े आठ लाख रोहिंग्या बांग्लादेश और म्यांमार सीमा पर स्थित शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। इसमें से अधिकांश 2017 में म्यांमार की सैनिक कार्रवाई के कारण भागकर इस क्षेत्र में आए थे।

एक अन्य समाचार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने बांग्लादेश के साथ हुए शरणार्थियों के पुनर्वास समझौते की पुष्टि की है। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां इन शरणार्थियों को जबरन इन टापुओं पर भेज रही है। जबकि जिन शरणार्थियों को इन टापुओं पर भेजा गया था उनका कहना है कि ये टापू रहने के काबिल नहीं हैं और उनमें नागरिक सुविधाओं का अभाव है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश से जिन शरणार्थियों को इन टापुओं पर भेजा था उनमें से काफी भागकर मुख्य भूमि में आ गए हैं। पिछले महीने इन टापुओं से नावों पर भागकर आने वाले सैकड़ों शरणार्थी समुद्र में डूब मरे हैं। बांग्लादेश सरकार का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए बांग्लादेश को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है और वहां पर चल रहे कार्य की निगरानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी कर रहे हैं।

बलूचिस्तान में भीषण भूकंप

इंकलाब (8 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान में आए भीषण भूकंप के कारण 40 से 50 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है जबकि सैकड़ों घायलों को अस्पतालों में दाखिल करवाया गया है। जियो न्यूज के अनुसार क्वेटा, सिबी, जियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, सरब, लोरालाई और पिशीन क्षेत्रों में जबर्दस्त भूकंप महसूस किए गए। परंतु भूकंप के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हरनाई में हुआ जबकि इस कस्बे का पूरी तरह से नामोनिशान मिट गया है। बलूचिस्तान भूकंप के क्षेत्र में स्थित है। 1937 में बलूचिस्तान में आए भीषण भूकंप के कारण क्वेटा में 30 हजार से अधिक लोग मारे गए थे। पाकिस्तान सरकार के दावे के अनुसार हाल ही में जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता 6 रिक्टर स्केल का है और इसका केंद्र हरनाई में भूमि में दस किमी गहराई में था। पाकिस्तान सरकार ने आपात नियंत्रण अधिकरण के अलावा सैनिकों को भी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भेजा है। अभी मलबा में दर्जनों लोग दबे हुए हैं जिनको बाहर निकालने का काम राहत व बचाव टीमें कर रही हैं। सारे क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बंद कर दी

गई है। इमरजेंसी के कारण पाकिस्तान भर से डॉक्टरों और राहत व बचाव टीमों को वायुयान द्वारा बलूचिस्तान भजा जा रहा है। बलूचिस्तान के पुलिस महानिदेशक नासीर का कहना है कि जो क्षेत्र भूकंप से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं उनमें से अधिकांश पहाड़ी हैं और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं इसलिए वहां पर राहत व बचाव टीमों को भेजने में बेहद कठिनाई आ रही है। आर्मी हलीकॉप्टरों की सहायता से भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य और पानी पहुंचाया जा रहा है। सऊदी अरब सरकार ने बलूचिस्तान में हुए भूकंप पर पाकिस्तानी जनता के साथ संवेदना व्यक्त की है और उन्हें संपूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

पाकिस्तान गुप्तचर एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त

रोजनामा सहारा (7 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के प्रमुख के पद से हटा दिया है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इमरान खान फैज हमीद की अफगानिस्तान में गतिविधियों से नाराज थे इसलिए उच्च स्तर पर उन्हें इस महत्त्वपूर्ण पद से हटाने का फैसला किया गया है। अब वे पाकिस्तान सेना की पेशावर कोर के कमांडर होंगे। उनका उत्तराधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इमरान खान ने स्वयं की है। जनरल अंजुम रावलपिंडी जिले के गूजर खान के रहने वाले हैं। इससे पूर्व व कराची कोर के कमांडर थे। सितंबर 2019 में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर उन्नति दी गई थी। उनका संबंध पंजाब रेजिमेंट से है। वे ब्रिटेन स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्ट्डोज के प्रशिक्षित हैं। उन्हें आतंकवाद पर नियंत्रण करने और विदेशों में हिंसा और तोड़फोड़ की कार्रवाईयों का विशेषज्ञ माना जाता है। बलूचिस्तान में पनप रहे विद्रोह को उन्होंने फ्रंटियर कोर के महानिदेशक के रूप में बड़ी सख्ती से दबाया था। उन्हें कश्मीर का विशेषज्ञ और भारत के मामलों का भी खास जानकार माना जाता है।

पश्चिम एशिया

यहूदियों को मस्जिद अल–अक्सा में प्रार्थना की अनुमति

इंकलाब (9 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल के एक न्यायालय ने मस्जिद अल-अक्सा में प्रार्थना करने वाले यहूदियों के पक्ष में एक विवादित फैसला सुनाया है जिस पर फिलिस्तीनो अथॉरिटी ने सख्त विरोध प्रकट किया है। समाचार एजेंसियों के अनुसार इजरायल में रहने वाले रब्बी आर्यह लिप्पो ने मस्जिद अल-अक्सा के परिसर में यहूदियों के प्रवेश पर लगाई गई अस्थाई पाबंदी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए मजिस्ट्रेट ने इजरायल पुलिस को यह निर्देश दिया है कि अगर यहूदी मस्जिद अल-अक्सा में प्रार्थना करते हैं तो उसे अपराध न समझा जाए और न ही उन्हें यह प्रार्थना करने से रोका जाए।

1994 में जॉर्डन और इजरायल के बीच हुए समझौते के तहत मस्जिद अल-अक्सा परिसर में यहूदियों को प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी गई। इस क्षेत्र में सिर्फ मुसलमान ही नमाज अदा करते हैं, जबकि यहूदी पश्चिमी दीवार पर प्रार्थना कर सकते हैं। अदालती निर्णय पर विराध प्रकट करते हुए फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद इब्राहिम शतयेह ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि वह यहूदियों को मस्जिद परिसर में दाखिल होने से रोकने के लिए अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय यहूदियों को जबरन इस इमारत में प्रवेश करवाना है। इसलिए सभी अरब देशों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। मस्जिद अल-अक्सा के संरक्षक जॉर्डन ने भी अदालती फैसले को जॉर्डन और तेल अबीब के बीच हुई शांति संधि का उल्लंघन और मस्जिद अल-अक्सा की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति का संगीन अतिक्रमण करार दिया है। मस्जिद अल-अक्सा के मामले के वकील खालिद जबरका ने कहा है कि इजरायली न्याय वयवस्था को मस्जिद अल-अक्सा के मामलों में हस्तक्षेप करने और सदियों स वहां चली आ रही परंपराओं में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत के इस फैसले को उच्च नयायालय और फिलिस्तीनी अधिकरण से पुष्टि प्राप्त करनी होगी। किंतु अरबों का कथन है कि

इस फैसले की आड़ लेकर इजरायल मस्जिद अल-अक्सा पर अवैध कब्जा कर सकता है। मस्जिद अल-अक्सा के इमाम इकरीमा सईद साबरी ने कहा है कि इजरायल की किसी अदालत या किसी अन्य संगठन को मस्जिद अल-अक्सा के बारे में कोई भी फैसला करने का अधिकार नहीं है। मस्जिद अल-अक्सा सिर्फ मुसलमानों का पवित्र स्थान है और इस पर यहूदियों का कोई अधिकार नहीं है और इसकी रक्षा करना दुनिया भर के मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है।

इंकलाब (3 अक्टूबर) के अनुसार इस्लामिक सहयोग संगठन ने मस्जिद अल-अक्सा पर यहूदी सरकार के अतिक्रमण की घोर निंदा की है और आरोप लगाया है कि इजरायल यरुशलम से फिलिस्तीनियों को जबरन निकाल रहा है। यहूदी बस्तियों का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है और फिलिस्तीनियों के वंशान्मुलन का अभियान चल रहा है और इस पवित्र नगर का भौगोलिक नक्शा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस संगठन ने मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थान मस्जिद अल-अक्सा पर इजरायल का ध्वज लहराए जाने की निंदा की है और विश्व भर के देशों से अपील की है कि वे इजरायल को इस मस्जिद का अपमान करने से रोकें। दूसरी ओर फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन करके यहूदियों के प्रयासों की निंदा की है।

फिलिस्तीनी सूचना केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार यहूदी अतिक्रमण के खिलाफ फिलिस्तीन के विभिन्न क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों ने उग्र प्रदर्शन किए। इस पर इजरायल ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें सात फिलिस्तीनी घायल हो गए। यहूदी सरकार ने ड्रोन द्वारा प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस बरसाए। इस दौरान एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त होकर बर्बाद हो गया। यहूदी सैनिकों ने अल-खलील नामक नगर पर हमला किया जिस पर उनकी फिलिस्तीनी नौजवानों से जबर्दस्त झड़पें हुईं। इसमें आठ फिलिस्तीनी मारे गए। मुस्लिम अतिवादी संगठन हमास ने आरोप लगाया है कि गाजा में इजरायली जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमास के नेता मुशा मोहम्मद अबु मरजूक ने घोषणा की है कि हमास चुप नहीं रहेगा और वह इजरायलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

ईरान और तुर्की के साथ संबंध सुधारने हेतु यू.ए.ई. प्रयत्नशील

सियासत (5 अक्टूबर) क अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने अन्य अरब देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए जोरदार अभियान शुरू कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल-नहयान के राजनयिक सलाहकार अनवर गर्गाश का कहना है कि वर्तमान हालात को देखते हुए यह जरूरी है कि पुरानी नीतियों पर पुनर्विचार किया जाए ताकि ईरान और तुर्की के साथ लंबे अरसे से चल रहे विवादों को वार्तालाप द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाए। ताकि इस क्षेत्र में कोई नया टकराव पैदा न हो। उन्होंने यह संकेत दिया है कि हम अमेरिका और चीन के बीच होने वाली संभावित शीत युद्ध से अलग रहना चाहते हैं। उन्होंने एक संवाददाता सम्मलन में कहा कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते हुए तनाव के बारे में हमलोग चिंतित हैं। खाड़ी देशों के चीन के साथ बहत अच्छे और मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। दूसरी ओर ये सारे देश अमेरिका की सैनिक सहायता और उसके संरक्षण के भी मोहताज हैं।

अनवर गर्गाश ने कहा कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की ओर से ईरान के साथ

परमाणु संधि को पुनः बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि अफगानिस्तान में अब तालिबान के सत्ता में आने के बाद अनेक नई समस्याओं ने जन्म लिया है। हमारे क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी और वर्चस्व के कारण अनेक तरह की कठिनाईयां पैदा होने की संभावना है। इसलिए यह कहना कठिन है कि हालात क्या मोड़ लेते हैं। बदलते हुए हालात के कारण हमें अपने इस सारे क्षेत्र को समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय होने की जरूरत है। अफगानिस्तान में जो रिक्तता पैदा हुई है उससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए हम गत कई महीनों से ईरान और तुर्की के साथ वार्ता द्वारा तनाव को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की यह धारणा है कि जब तक ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर लगाम नहीं लगाई जाती परमाणु संधि अर्थहीन है। तुर्की ने हाल ही में मिस्र, इख्वानुल मुस्लिमीन और सऊदी अरब के बारे में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने का जो सिलसिला शुरू किया है वह स्वागत योग्य है। उससे हम कोई रास्ता निकाल सकेंगे। अभी तक तुर्की के साथ हमारी वार्ता सकारात्मक रही है। मगर परेशानी की बात यह है कि क्या ईरान इस क्षेत्र के बारे में अपनी नीति में कोई परिवर्तन करेगा? हालांकि यह साफ है कि ईरान भी बदलती हुई परिस्थितियों के बारे में फिक्रमंद हैं। कोरोना महामारी के बाद बदलते हुए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हमारे लिए महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। हम अमेरिका और चीन के बीच होड़ में फंसने से बचना चाहते हैं।

इत्तेमाद (5 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि हम ईरान के साथ विवादों को सुलझाने के लिए जो बातचीत कर रहे हैं वह अभी प्राथमिक दौर पर है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के सुरक्षा अधिकारी जोसेप बोरेल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम यह प्रयास कर रहे हैं कि ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु शक्तिकरण की नीति पर पुनर्विचार करे। क्योंकि इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है आर सशस्त्रीकरण की नई दौर शुरू हो सकती है। हमारा यह भी प्रयास है कि यूरोपीय यूनियन यमन में युद्ध विराम के बारे में दबाव डाले। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पर हूतियों के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इस अवसर पर जोसेप बोरेल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के देश सऊदी अरब के सबसे बड़े भागीदार हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि यमन का विवाद शांतिपूर्ण ढंग से हल हो। सऊदी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हम ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा यह प्रयास है कि सुन्नी और शिया देशों के आपसी मतभेद दूर हों और सभी मुस्लिम देश एकजुट हों। ■

बहरीन में इजरायली दूतावास का उद्घाटन

सियासत (3 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल के विदेश मंत्री यायर लापिड ने बहरीन की राजधानी मनामा में अपने देश के दूतावास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बहरीन के विदेश मंत्री अबदुल लतीफ बिन राशिद जियानी भी मौजूद थे। इसके बाद इजरायल के विदेश मंत्री ने बहरीन के शाह हामद बिन इसा अल-खलीफा से भी मुलाकात की। बहरीन और इजरायल के बीच गत वर्ष हुए डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी इजरायली मंत्री का बहरीन का यह पहला दौरा है। इजरायल के मंत्री के आने के खिलाफ और मनामा में इजरायली दूतावास के उद्घाटन के खिलाफ बहरीन के विभिन्न नगरों में नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन

किया। इजरायल और बहरीन के बीच इस अवसर पर पांच समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, जिनमें अस्पतालों, पीने के पानी और बिजली के उत्पादन में दोनों देशों का सहयोग शामिल है।

इजरायली प्रवक्ता ने कहा कि बहरीन अर्थव्यवस्था और तकनीक के मामले में इजरायल का सहयोग चाहता है और हम उन्हें यह सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अब तक 12 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिनका संबंध परिवहन, कृषि, सूचना तकनीक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। दोनों देशों के बीच वायु सेवा भी शुरू हो गई है। बहरीन की सरकारी एयरलाइंस गल्फ एयर ने तेल अबीब के लिए उड़ान शुरू कर दी है। अमेरिका के दबाव के कारण बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध इजरायल के साथ स्थापित हुए हैं। मगर जनता इसका विरोध कर रही है।

ईरान द्वारा रूस के साथ संबंध सुधरने का प्रयास

इंकलाब (7 अक्टूबर) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दोल्लाहियान ने हाल ही में मास्को का दौरा किया और रूस से यह अनुरोध किया कि वह इजरायल की आक्रामक हरकतों पर कड़ी नजर रखे। क्योंकि इजरायल अमेरिका के सहयोग से अरब जगत के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। समाचारों के अनुसार रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के विशेष आमंत्रण पर ईरान के विदेश मंत्री मास्को पहुंचे थे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वे रूस के साथ परमाणु समझौते और अन्य सुरक्षा मामलों में सहयोग के बारे में वार्ता करेंगे। जबकि रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ईरान के विदेश मंत्री के दौरे का संबंध इस क्षेत्र में आतंकवाद के विस्तार को रोकना, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना ओर अफगानिस्तान के नवनिर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना तथा सीरिया की समस्या को हल करने के लिए ईरान और रूस का प्रयास आदि मुद्दे शामिल हैं।

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार रूस ने दावा किया है कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान ने अपनी सीमा पर भारी संख्या में सेना को तैनात किया है। इस क्षेत्र के तनाव में निरंतर वृद्धि हो रही है। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा पर बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए ईरान ने इस सीमा के समीप अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैनिक अभ्यास शुरू कर दिए हैं और ईरान भी इस सीमा पर अपने सैनिकों को भारी संख्या में ले आया है। इससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। ईरान ने अपने स्पेशल फोर्स यूनिट के सैकड़ों फौजियों को अफगान-ताजिकिस्तान सीमा के समीप स्थित अपने क्षेत्र में सैनिक अस्त्र-शस्त्रों को इकठ्ठा करना शुरू कर दिया है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमान ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के कारण इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान की नई सरकार का मान्यता देने से इंकार कर दिया है। तालिबान सरकार ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि ताजिकिस्तान को हमारे मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

कौमी तंजीम (8 अक्टूबर) के अनुसार ईरान ने अजरबैजान में इजरायल के बढ़ते हुए प्रभाव पर कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने मास्को में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि इजरायल के दबाव पर अजरबैजान ने ईरान की सीमा पर न सिर्फ सैनिक अभ्यास ही शुरू कर दिए हैं बल्कि वहां पर सैनिकों को भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है और हाल ही में इजरायल के विशेषज्ञों ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया था। मीडिया के अनुसार ईरान तुर्की के साथ मिलकर इस क्षेत्र में सैनिकों को इकठ्ठा कर रहा है। ईरान और उसके उत्तरी पड़ोसी देश में इसलिए तनाव बढ़ रहा है कि ईरान में अजरबैजान के अजेरी कबीला के लोग भारी संख्या में हैं और इजरायल उनको ईरान के खिलाफ भड़का सकता है।

इत्तेमाद (7 अक्टूबर) के अनुसार रूस के विदेश मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से रूस के व्यापार में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका या पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर डाले गए दबाव को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और ईरान को पूरा सहयोग देंगे। हम

ईरान और तुर्की के साथ अपने सहयोग को जारी रखेंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 अक्टूबर) के अनुसार ईरान ने वेनेजुएला को भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र सप्लाई करने शुरू किए हैं। कोलंबिया के एक समाचारपत्र के अनुसार ईरान की एक विमान कंपनी फास एयर कशम के कई बोइंग विमान भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र लेकर वेनेजुएला के सैनिक अड्डे लिबर्टाडोर पर उतरे हैं। इन विमानों द्वारा ईरान ने 2000 मिसाइलें, 400 बम और अन्य अस्त्र-शस्त्र सप्लाई की हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन अस्त्र-शस्त्रों का प्रशिक्षण देने के लिए ईरानी सैनिक और ईरानी गुप्तचर विभाग के उच्चाधिकारी

भी भारी संख्या में वेनेजुएला पहुंचे हैं। कहा जाता है कि ईरान ने यह कदम अमेरिका पर दबाव डालने के लिए उठाया है।

ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री

इंकलाब (1 अक्टूबर) के अनुसार अरब देश ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने संसद को भंग करने और देश के प्रधानमंत्री हिचेम मचिचो को बर्खास्त करने के बाद एक लगभग अज्ञात महिला नजला बौडेन रोमधाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कैस सईद ने एक फरमान जारी करके नजला बौडेन को नया मंत्रिमंडल गठित करने का अधिकार दिया है। राष्ट्रपति ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि अरब देशों में पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री के पद पर मनोनीत किया गया है। उन्होंने यह आशा व्यक्त की है कि वे देश के प्रशासनतंत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार और अफरातफरी को सख्ती से कुचलकर देश की राजनीति को नया मोड़ देंगी।

कहा जाता है कि यह महिला कभी भी ट्यूनीशिया की राजनीति में सक्रिय नहीं रहीं। इसलिए उनकी नियुक्ति पर विभिन्न अटकलें लगाई जा रही हैं। इस महिला की उम्र 63 वर्ष की है। व पेशे से इंजोनियर हं। वे ट्यूनीशिया के केन्द्रीय क्षेत्र कैरौन में 1958 में पैदा हुई थीं और वह नेशनल इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ ट्यूनीशिया में प्राध्यापक थीं। 2011 में उन्हें उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था।

सियासत (5 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद किसी महिला को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने वाला ट्यूनीशिया तीसरा मुस्लिम देश है। मुस्लिम देशों में पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थीं जिन्हें आतंकी हमले में मार दिया गया था। बांगलादेश में शेख हसीना सत्तारूढ़ हैं जो बांगलादेश के जनक शेख मुजीबुर्रहमान की बेटी हैं। ट्यूनीशिया की जनसंख्या 1 करोड़ 10 लाख है। वहां की सरकार कोरोना से निपटने में विफल रही थी। इसलिए जनभावना पुरानी सरकार के खिलाफ थी। इसका लाभ उठाकर राष्ट्रपति कैस सईद ने 2014 का संविधान रद्द करके सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का दावा है कि नई प्रधानमंत्री को क्योंकि राजनीति का कोई अनुभव नहीं है इसलिए वह देश के आर्थिक संकट और बढ़ती हुई महंगाई को रोक पाने में सफल नहीं हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त उन्हें संसद में किसी भी पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं है।

सऊदी अरब में 16000 घुसपैठिए गिरफ्तार

इंकलाब (10 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों के खिलाफ

चलाए जा रहे अभियान के सिलसिले में गत एक सप्ताह में 16 हजार 151 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति 1970 के दौरान लागू कानून का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से सऊदी अरब में दाखिल हुए थे। गिरफ्तार किए गए 7000 लोग सऊदी अरब के श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर नौकरी कर रहे थे। जबकि 8 हजार लोगों को सीमाओं पर अवैध रूप से पवेश करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से 44 प्रतिशत यमन के 54 प्रतिशत इथियोपिया के और 2 प्रतिशत अन्य देशों के नागरिक हैं। सऊदी अरब से अन्य देशों में जाने का प्रयास करने वाले 26 लोगों को सीमा पार करते हुए गिरफ्तार किया गया। उन्हें पनाह देने वाले 13 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 69 हजार लोगों को सऊदी अरब में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार करके देश से निष्कासित किया जा चुका है।

अन्य

मुसलमानों में तलाक की बढ़ती घटनाओं पर चिंता

सियासत (12 अक्टूबर) के अनुसार गुलबर्गा में मुसलमानों के एक सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न वक्ताओं ने मुसलमानों में तलाक की बढती हुई घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उदाहरण के तौर पर वारंगल में पिछले छह महीनों में तलाक की 34 घटनाएं हुईं, जबकि निकाह सिर्फ एक ही हुआ। सियासत के प्रबंध संपादक जहीरूद्दीन अली खान ने कहा कि मुस्लिम छात्राएं गंभीरता से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। जबकि मुस्लिम लड़कों को शिक्षा प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं है। वे इस्लाम से दिन-प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं और नशेड़ी बन गए हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे अपने बच्चों की देखभाल पर ज्यादा ध्यान दें और उन्हें लव जिहाद के चंगुल में फंसने से रोकें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में दहेज की बढ़ती हुई कुप्रथा के कारण मुसलमान लड़कियां गैरमुसलमान लड़कों के चंगुल में फंसती जा रही हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इस्लाम और उसकी बेटियों को बचाने के लिए विवाह शादियों पर होने वाली फिजुलखर्ची को रोका जाए और रसूल पाक की परंपराओं का अनुकरण करते हुए सभी निकाह बेहद सादगी से मस्जिदों में करवाए जाएं।

चारमीनार निर्माण के 430 वर्ष

सियासत (11 अक्टूबर) के अनुसार दुनिया भर में हैदराबाद की पहचान बने चारमीनार के निर्माण को 430 वर्ष गुजर चुके हैं। कहा जाता है कि 9 अक्टूबर 1591 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। यह सुल्तान कुली कुतुब शाह द्वारा बनाई गई नई राजधानी हैदराबाद का पहला भवन था। इसका निर्माण सुल्तान ने क्यों करवाया था। इसके बारे में विभिन्न तरह की चर्चाएं गर्म हैं। इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान ने इसका निर्माण अपनी प्रेमिका भागमती की इच्छा के अनुसार करवाया था।

इसका नक्शा ईरान के एक वास्तुकार मीर मोमिन अस्तराबादी ने तैयार किया था और यह दो वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार 1687 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा पर विजय प्राप्त किया था तो उसने एक फरमान जारी करके चारमीनार को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। मगर जब उसे यह जानकारी मिली कि इस मीनार के ऊपर एक मस्जिद भी स्थित है तो उसने इस मीनार को ध्वस्त करने के फरमान को रद्द कर दिया।

अशरफ गनी पर 16 करोड़ डॉलर चोरी का आरोप

रोजनामा सहारा (12 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के एक सुरक्षाधिकारी ने अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी के इस आरोप की पुष्टि की है कि पूर्व अफगान राष्ट्रपति काबुल से फरार होते समय अपने साथ सोलह करोड़ डॉलर ले गए थे। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल पीराज अता शरीफी ने कहा है कि उनके पास इस बात के वीडियो क्लिप हैं जिसमें पूर्व राष्ट्रपति को यह धनराशि अपने साथ दुबई ले जाते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास राष्ट्रपति भवन की एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, जिससे पता चलता है कि अफगान बैंक का एक अधिकारी वहां से भारी धनराशि लेकर अशरफ गनी के पास आया था और उन्हें यह धनराशि दी थी। अशरफ गनी पर यह आरोप लगाया गया था कि वे 16 करोड़ डॉलर हेलीकॉप्टरों में भरकर दुबई रवाना हुए थे। मगर उन्होंने बाद में इस आरोप का खंडन किया था। अब उनके पूर्व सुरक्षा सलाहकार ने उनका पर्दाफाश कर दिया है।

कुरान की अनमोल पांडुलिपि प्रदर्शनी में पेश

इंकलाब (11 अक्टूबर) के अनुसार दुबई एक्सपो 2020 नामक प्रदर्शनी में 18वीं शताब्दी के कुरान की एक पांडुलिपि पेश की जा रही है जो कि कभी अमरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन की मिल्कियत हुआ करती थी। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कुरान की यह पांडुलिपि अमेरिकी कांग्रेस के पुस्तकालय के अनमोल खजानों में शामिल है। इसे वहां से लाकर इस प्रदर्शनी में पेश किया जा रहा है। कहा जाता है कि अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति ने कुरान की इस पांडुलिपि को खरीदा था। कोरोना महामारी के कारण एक वर्ष के बाद दुबई में इस्लामिक विरासत की इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।

सऊदी अरब में 200 महिलाएं मस्जिदों की देखभाल के लिए नियुक्त

इंकलाब (13 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार 200 से अधिक महिलाओं को देश की दो सबसे बड़ी मस्जिदों के कर्मचारी के रूप में भर्ती किया गया है। ये महिलाएं इस्लाम में डॉक्टरेट की डिग्री धारक हैं। मस्जिद अल-हरम के इमाम डॉ. अब्दुल रहमान अल-सुदैस ने कहा है कि जिन महिलाओं को मस्जिदों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है उनमें से अधिकांश युवा हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों में संभवत: सऊदी अरब पहला देश है, जिसमें महिलाओं को मस्जिदों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया ह।

अमेरिका में मुसलमानों के कब्रिस्तान को आग लगाने का प्रयास

सियासत (8 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका के राज्य मिनेसोटा में मुसलमानों के कब्रिस्तान को कुछ इस्लाम विरोधी तत्वों ने ध्वस्त करने की कोशिश की। मिनेसोटा काउंसिल ऑफ अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशन ने एक वक्तव्य में कहा है कि राज्य के कैसल रॉक नामक कस्बे में कुछ शरारती तत्वों ने कब्रिस्तान के आसपास वाहनों के सैकड़ों पुराने टायरों का जमा कर उनमें आग लगा दी, जिससे कबिस्तान को भारी क्षति पहुंची है। अमेरिकी मुसलमानों ने सरकार से मांग की है कि मुस्लिम विरोधी शरारती तत्वों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

RNI No. DELHIN/2017/72722

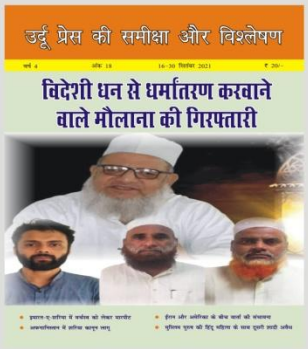

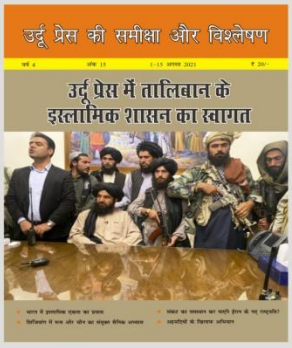

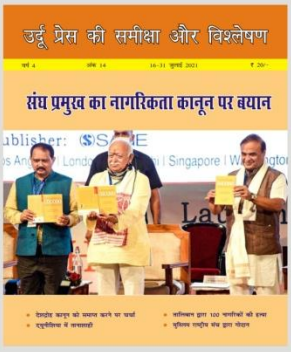

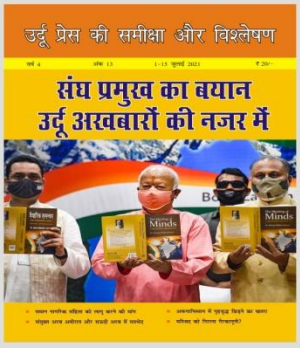

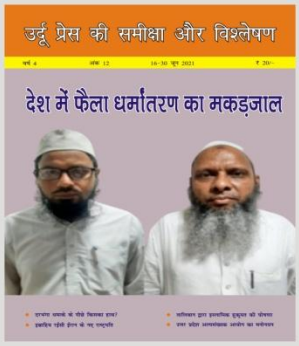

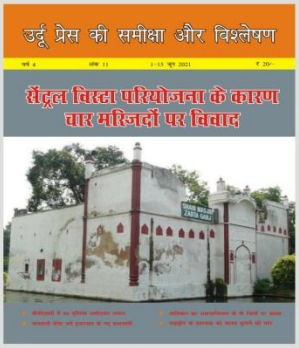

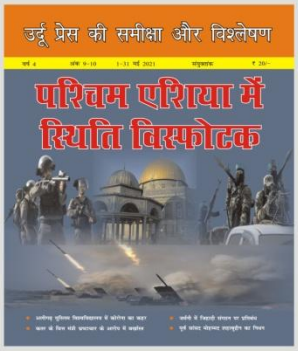

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in